मन्त्री शिवचरण शर्मा किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत सप्ताह, एन आईटी से विधायक एवं राज्य के श्रम मन्त्री शिवचारण लाल शर्मा ने प्रेस वार्ता के द्वारा क्षेत्र में कराये गये फ़र्जी विकास कार्यों के लिये अपनी पीठ थपथपाई। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ने की बात तो कही परन्तु किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, यह नहीं बताया।

जाहिर है चुनाव के वक्त हवा का रूख देख कर ही वे कोई फ़ैसला करेंगे। निर्दलीय विधायक निर्वाचित होने के चलते वे किसी पार्टी विशेष से बंधे तो है नहीं, इसलिये उन्हें पूरी छूट है। जिस टिकट पर अधिक लाभ दिखेगा उसी पर लड़ लेंगे। वैसे भी चाहे किसी पार्टी से लड़ लो नीतियां तो सब की एक जैसी ही हैं यानी कि जनता को लूटने व बेवकूफ़ बनाने की।

गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा को देखते हुए शर्मा जी ने पूरा मन बना लिया था कि भाजपा में जाना ही लाभ प्रद रहेगा। इसी के चलते एक बेटे ने कांग्रेस त्याग कर भाजपा में प्रवेश पा लिया और घर पर भाजपा का झंडा भी लगा लिया। इस बाबत शर्मा जी कहते हैं कि बालिग बेटे को पूरा अधिकार है कि वह चाहे जिस पार्टी में जाये।

जहां तक बालिग बेटे के अधिकार की बात है वह तो ठीक है परन्तु वह बेटा अपने मन्त्री बाप के नाम पर जो सत्ता की दुकानदारी चला रहा है वह कहां तक उचित है ?

दिन दहाड़े मज़दूर पर हमला अस्पताल की उदासीनता से मौत

फ़रीदबाद (म.मो.) दिनांक 15 जुलाई को मुर्दा मवेशी उठाने वाले मज़दूरों पर थाना सूरजकुंड के गांव अनंगपुर इलाके में कातिलाना हमला किया गया जिसमें एक मज़दूर देवानंद की दूसरे दिन मौत हो गयी।

ओल्ड फ़रीदाबाद नगर निगम द्वारा कर्जन नामक एक ठेकेदार को मुर्दा मवेशी उठाने का ठेका दिया गया है। इसके एवज में कर्जन साढे 12 लाख वार्षिक निगम को देता है। लेकिन ये मुर्दा मवेशी कहां डाले जायेंगे इसके लिये निगम द्वारा कोई जगह सुनिश्चित नहीं है, जिसे लेकर अक्सर आस-पास के ग्रामीण, ठेकेदार के कारिंदों से लड़ते-भिड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसी खूनी लड़ाई पहले कभी देखने को नहीं मिली।

15 जुलाई को सायं 4 बजे जब देवानंद व 4 अन्य कारिंदे एक मुर्दा मवेशी को डालने जा रहे थे तो अरावली स्कूल से पाली को जाने वाली सड़क पर लाठियों से लैस 10-12 गुंडों ने इन्हें घेर लिया। तीन कारिंदे जान बचा कर भागे लेकिन देवानंद व एक अन्य काबू आ गये। दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा। भागे हुए तीनों कारिंदे अरावली पाली रोड तिराहे पर बने पुलिस नाके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

पैदल पुलिस ने जैसे-तैसे किसी वाहन को पकड़ा और मौके पर पहुंच कर दोनों घायल पड़े कारिंदों को गाड़ी में डलवाकर बी के अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में स्टाफ़ एवं साजोसामान के अभाव में देवानंद को कोई समुचित इलाज नहीं मिल सका। उसके बुरी तरह से कुचले हुए हाथ पैरों से खून बहता रहा, लेकिन अस्पताल के पास इसे रोकने की कोई व्यवस्था न होने के चलते देवानंद को सफ़दरजंग दिल्ली रैफ़र कर दिया गया। लेकिन वहां पहुंचते इतना खून बह चुका था कि 16 जुलाई को दिन के 11 बजे उसकी मौत हो गयी।

दरअसल उसकी मौत ग़रीबी के चलते हुई। यदि वह साधन सम्पन्न होता तो उसे बी के अस्पताल के बजाय एशियन अस्पताल में ले जाया जाता, जहां पैसा तो अंधा लगता लेकिन इलाज तुरन्त शुरू हो जाने से जान बच जाती। आये दिन दिखने वाले ऐसे उदाहरण हरियाणा सरकार की उस नम्बर वन चिकित्सा व्यवस्था का नंगा करते हैं जिसका ढोल भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रोज़ाना मीडिया के द्वारा पीट रहे हैं।

उधर हत्या की तफ़्तीश कर रही पुलिस का ध्यान नगर निगम के ही एन आइटी जोन के ठेकेदार इलियास की ओर भी गया है। क्योंकि असल में ओल्ड का ठेका तो पहले इलियास के नाम पर ही छुटा था, लेकिन मई माह में उस पर हुए एक हमले के बाद उसने यह ठेका कर्जन को बेच दिया था।

स्मैकियों द्वारा दलित की दुकान में घुसकर हमला: पुलिस उदासीन

करनाल: (प्रवीण कुमार) यू तो मुख्यमंत्री हुड्डा चुनावी घोषणाओं में व्यस्त है और हरियाणा नम्बर 1 का ढोल पीटते नहीं थकते। वही हरियाणा का पुलिस विभाग कानून एवं व्यवस्था में फिस्ड्डी बनने में जी जान से जुटा है।

ताज़ा घटना ज़िला करनाल के एक गांव सीघड़ा में घटी है जहां आधी रात के समय तीन सिख युवक भारत भूषण नाम के एक दुकानदार को आधी रात को जबरन दुकान खोलने को मजबूर करते हैं बार-बार दरबाजा खटखटाने पर छोटा भाई दुकान खोलता है तो उससे युवकों द्वारा सिगरेट मांगी जाती है। दुकानदार द्वारा सिगरेट न होने की बात जब कही जाती है तो युवकों ने भारत भूषण के भाईयों को पीटना शुरू कर दिया, बचाने आये पिता मोहन लाल व उसकी पत्नी सुशीला, बेटी अनुबाला के दोनों भाईयों पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। यह पूरा परिवार नीसिंग अस्पताल गया जहां एमएलआर काट खानापूर्ति कर उन्हें करनाल के सिविल अस्पताल रैफर कर दिया। इस दौरान एम एल आर की कापी अस्पताल द्वारा स्थानीय थाना में भेज दी गई। परन्तु थाना वालों ने प्राथमिकी दर्ज करना तो दूर जिन्हें मारा-पीटा गया उनके ब्यान लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी।

घटना 3 तारीख की थी और 4 तारीख तक पुलिस द्वारा कोई ब्यान नही लिये गये। जब इस घटना का पता इस संवाददाता को चला तो पुलिस अधीक्षक करनाल को सूचित किया तब जाकर नीसिंग पुलिस जागी और नीसिंग थाना के जांच अधिकारी सुखवाल एएसआई को इस घटना बाबत मोबाईल नम्बर 9996581661 पर पूछा तो कहा कि हमने 323 की रपट दर्ज कर ली है। परन्तु नीसिंग पुलिस ने एफ़आई आर दर्ज नहीं की। जब सुखपाल ए एस आई से पूछा कि एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं की तो उसने बताया कि एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद एफ़आईआर दर्ज की जायेगी जब सुखपाल ए एस आई से कहा गया कि 452 तो बनती ही है तो इस पर कहा कि फ़िर वही वाक्य दोहराया कि रिपोर्ट आने दो फ़िर करेंगे। घटना में जबकि दुकानदार की दुकान आधी रात को खुलवाकर कथित अभियुक्तों द्वारा मारपीट की गई। जांच अधिकारी ने इसे दुकान के बाहर गेट पर बताकर 452 से केस को कमज़ोर करने की कोशिश करता नज़र आया।

घटना का दूसरा पहलू है कि अक्सर सिख लोग सिगरेट नही पीते फ़िर आधी रात को दुकान खुलवाकर सिगरेट क्यों मांगी ? दरअसल ये स्मैक पीने का मामला लगता है। क्योंकि स्मैक सिगरेट में भरकर पी जाती है। अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो शायद उनके हाथ कुछ नशीली वस्तुयें भी लग जाती। पर पुलिस का मकसद नशा बन्द करवाना नही पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी नशा अपने पांव जल्दी से फ़ैला रहा है और यह घटना भी सिर्फ मारपीट का मामला भर नही है सीधे सीधे नशे से जुड़ा हुआ मामला लगता है। अंतत:पुलिस ने 15 तारीख को 323, 325, 334 धारा में मुकदमा दर्ज किया। खबर लिखे जाने तक अभी 2 को ही गिरफ़्तार किया गया है।

निजी अस्पतालों की अंधी लूट के शिकार बनते मरीज़

फ़रीदाबाद (म.मो.) पंचसितारा होटलों की तर्ज पर अस्पताल बनाकर मरीज़ों से लूटमार करने में अस्पताल मालिक जम कर लगे पड़े हैं। इस कड़ी में शहर का फोर्टिस हॉस्पिटल लूटमार में भला किसी से पीछे क्यों रहे। अस्पताल प्रशासन की लूटमार का नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब दिनांन 09-07-2014 को पेट दर्द की शिकायत लेकर 5 नं. एम ब्लॉक का रहने वाला एक व्यक्ति फोर्टिस हॉस्पिटल में चैकअप करवाने गया। एमरजैंसी में डॉक्टरों के चैक करने के बाद उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। दिनांक 10-07-2014 से लेकर 13-07-2014 तक उस व्यक्ति के टैस्ट पर टैस्ट किए गए। बावजूद इतना होने के फोर्टिस के अनुभवी डॉक्टरों को चार दिन तो बीमारी का पता लगाने में लग गए। जब बीमारी का पता चला तो सामने आया कि एक मामूली पेट दर्द था जो कि इन्फैक्शन के कारण हुआ था। मरीज़ का 40,000 से ऊपर तक का बिल बन चुका था। मरीज़ ने दिनांक 14-07-2014 को जबरदस्ती अस्पताल से छुट्टी ली, जबकि अस्पताल प्रशासन अभी मरीज़ को दो दिन और रखना चाहता था।

ऐसे ही दूसरा उदाहरण है सैक्टर 16 निवासी आयूष (बैड नं.-11) पर था जो कि 09-07-2014 से पहले ही फोर्टिस हास्पिटल में अपने पेट दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती था। उसे अपैन्डिक्स की शिकायत थी जिसके चलते डॉक्टर आयूष का भी टैस्ट करा कर बिल बढाने में लगे हुए थे। जब डॉक्टरों की निगरानी में भी आयूष का दर्द कम न हुआ तो उसके घरवालों ने नर्सों व राउंड पर आए डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। अपने बच्चे को डिस्चार्य करने के लिए कहा। जब ये सारा मामला शांत हुआ तो वहीं साथ के बैड पर मरीज़ ने उसे कहा कि आप अपने घर के पास मैट्रो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। उस पर आयूष की मां बोली फोर्टिस हॉस्पिटल चोर है तो मैट्रो वाले डाकू हैं। उन्होंने मेरे पति के जबरदस्ती स्टन डाल दिए। जबकि अन्य डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर हमें बताया था कि स्टन की कोई जरूरत ही नहीं थी।

इसी तरह अलीगढ़ से आये राजकुमार जो कि बावासीर से पीड़ित थे, का ऑपरेशन फोर्टिस के डॉक्टर तलवार ने किया। जब डॉक्टर तलवार ऑपरेशन के दो दिन बाद राजकुमार को चैक करने आए तो उन्होंने राजकुमार को बताया कि हमने जो आपका ऑपरेशन साइड का किया था वैसा ही मस्सा लैफ्ट साइड में भी हो गया है। जिसका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। जिस पर राजकुमार डॉक्टरों पर भड़क गया। जब डॉक्टरों ने राजकुमार का गुस्सा देखा तो वे समझ गए जिस पर डॉक्टर तलवार ने राजकुमार से कहा कि घबराओ नहीं हम कोशिश करेंगे कि ये दवाईयों से ही ठीक हो जाए और वह हो भी गया। मात्र दो दिन में राजकुमार का 50000 से ऊपर का बिल बन चुका था। लेकिन अगले 50000 के बिल से वह बच गया।

बड़े-बड़े दावे करने वाला फोर्टिस अस्पताल जो बेड के मरीज़ों से हज़ारों रुपए रोज़ाना वसूलता है, वहां पांच दिन में राजनन्दा वार्ड के वैड नं. 15 का पिलोकवर नहीं बदला गया। जिस पर मरीज़ ने अस्पताल के सभी लोग़ों को बोला। टॉयलेट, बाथरूम की हालत बादशाह खान अस्पताल जैसी बनी हुई है। राजनन्दा वार्ड के पंखे के रैगुलेटर ही नहीं है अगर किसी मरीज़ को पंखा तेज़ या कम करना है तो वह नहीं कर सकता। ए.सी. की हालत तो ऐसी ही है पानी बाहर की जगह अन्दर कमरे में फैलता है

दरअसल मुनाफ़ाखोरी की अंधी दौड़ में ये सभी चिकित्सा व्यापारी एक ओर तो सेवा की गुणवत्ता घटाते जा रहे हैं और दूसरी ओर मरीज़ का शीघ्रातिशीघ्र इलाज शुरू करने की बज़ाये उसके टैस्ट पर टैस्ट केवल इस लिये किये जाते हैं कि बिल बनने का मीटर घूमता रहे। इसके चन्द नामी डॉक्टरों को छोड़कर बाकी स्टाफ़ का भी भरपूर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। स्टाफ़ द्वारा जरा सी आवाज़ उठाने पर अस्पताल प्रशासन एवं सरकार द्वारा उनका दमन शुरू कर दिया जाता है।

द डर्टी पॉलिटिक्स

वर्तमान समाज पूंजीवादी समाज है। इस समाज में जितने भी पूंजीपति व पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं उन सबका मुझे एक ही लक्ष्य नज़र आता है-वह है अधिक से अधिक भ्रष्टाचारी, गुण्डों, दबंगों का राजनीति में प्रवेश। इसलिये राजनीति को इस कदर डरावना बनाया जा रहा है कि सामान्य लोग़ों को राजनीति (डर्टी) यानी गंदी लगने लगती है। और समाज में से वही लोग चुनाव लड़ते हैं जो अधिक से अधिक पैसे वाले हैं या फ़िर जो गुण्डे या फिर दबंग हैं। ये लोग ही राजनीतिक पार्टी के साथ अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। इस कदर दबंग, गुण्डे, राजनीति में घुस जाते हैं तो जनता को लगता है कि राजनीति सिर्फ इन्हीं लोग़ों की है। इस तरह से यही लोग बार-बार चुनाव लड़ते हैं जिससे वंशवाद को बढावा मिलता है। समाज में ग़रीब या मज़दूर तबके के लोग उनसे हर बार के चुनावों में यही आशा लगाये रखते हैं कि वे विकास करेंगे। दरअसल ये नेता विकास तो करते हैं किन्तु अपना तथा पूंजीपति की पूंजी का। वही नेता सबसे अच्छा नेता होता है जो निजीकरण को बढावा दे तथा पूंजीपति के हित में कार्य करे।

नेता लोग देश व राज्य में बेरोजगारी को बढावा देते हैं जिससे पूंजीपतियों को अपने मुंह मांगे दाम पर अच्छे तथा कुशल मज़दूर मिल जाते हैं। जिनका वह बेतहाशा शोषण कर मुनाफ़ा कमाते रहते हैं। अगर कोई मज़दूर शोषण का विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिससे मज़दूर का परिवार भुखमरी का शिकार हो जाता है। और दूसरी ओर नेता अपनी तिजोरियों में वृद्धि करता है। वह पांच साल तक जनता को अधिक से अधिक नोचने-खसोटने में लगा रहता है क्योंकि उसे पता है कि लोग़ों को यह अधिकार ही नहीं है कि वे अपने द्वारा चुने गये नेता को वापस बुला सकें। इस प्रकार चुनावों द्वारा वही लोग चुने जाते हैं जो लोग पूंजीपति वर्ग के हित में अच्छे से काम कर सकें यानी नेता वही जो दबंग, गुण्डा और पैसे वाला। इस प्रकार आम जनता की नज़रों में राजनीति को एक गंदी चीज़ बनाया जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति गंदी नहीं है बल्कि इसे गंदा बनाया जा रहा है। ताकि लोग लोकतंत्र के झूठे माहौल में पूंजीपति के गुलामी करें।

उमेश, नागरिक

राजैनितक झल्लाहट

भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, 'लोग दो महीने प्याज न खाएं, उसके दाम अपने आप गिर जायेंगे' जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने फटकार लगायी कि, 'ऐसे याचिका दायर कर वह न्यायालय का कीमती वक्त न बरबाद करे'।

उच्चतम न्यायालय की जनहित याचिका पर की गयी टिप्पणी अहंकार से चाहे जितनी भरी हो परंतु आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हास्यास्पद है। पहली ही दृष्टि में कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायाधीश के अर्थशास्त्र के ज्ञान पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। पहले तो बेहद सामान्य तर्क के आधार पर कि 'यदि दो महीने तक प्याज न खाने के बाद जब आम लोग प्याज खायेंगे तो उसके दाम क्यों न ऊपर जायेंगे'। और फ़िर थोड़ा ज़्यादा तर्क करने पर हम पायेंगे कि चंद माह पहले प्याज 20 रुपये प्रति किलो आम बाजार में बिक रही थी और फ़िर उसके दाम यकायक चढते हुए 80 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गये और अब पुन: 20 रुपये प्रति किलो पर आ गये हैं। न्यायाधीश महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा उनके अर्थशास्त्र में कैसे हुआ ? क्या 20 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो पहुंचने के दौरान आम आदमी के प्याज की खपत कई गुना बढ़ गयी थी या कोई और चक्कर था।

राजनैतिक दृष्टि से देखें तो यह न्यायाधीश महोदय के उच्च वर्गीय सुविधा परस्त मोटी तनख्वाह वाले व्यक्ति का तर्क लगता है जिसे प्याज के दामों में 20-80 रुपये प्रति किलो पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वह आराम से मूर्खतापूर्ण उपदेश दे सकता है। कि जब किसी चीज का दाम उसकी पहुंच से बाहर हो तो वह उसका उपयोग न करे। क्या वह यह सब भी बोलेंगे जब अनाज के दाम ऐसे ही यकायक आसमान छू लेंगे। तब क्या वह यह कहेंगे कि ''रोटी मत खाओ! भात मत खाओ''। और यह एक सच है कि पिछले दिनों चावल के दामों में तेजी से बढोत्तरी हो रही है। इस महंगाई के जमाने में न्यायाधीश महोदय जनता से क्या-क्या बंद करवायेंगे।

असल में बात कुछ और ही है। और वह बात यह है कि न्यायाधीश महोदय की झल्लाहट शासक वर्ग की राजनैतिक झल्लाहट है। जब आम जनता के हितों में बात आती है तो वह झल्ला जाता है। वह रोटी मांगे तो वह झल्ला जाता है। वह रोजगार मांगे तो वह डंडा दिखाये। वह अपने हक-हकूक के लिए झंडा उठाये तो वह सीधे गोली चलाये।

न्यायाधीश महोदय विनम्रतापूर्वक कह सकते थे कि, 'भाई मेरे पास इस समस्या का समधान नहीं है'। परंतु वह तो सवाल उठाने वाले को ही डांटने लगे। सच यही है कि वे उसी राजनैतिक झल्लाहट को दिखला रहे थे जिसकी ऊपर चर्चा हो रही है।

ऐसी ही झल्लाहट किसी जमाने में नरसिंहराव ने तब दिखलायी थी जब किसी ने उनसे सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी मदों में कटौती करने पर आलोचना की तो वे बोल उठे, 'सरकार कोई धर्मशाला नहीं है'।

पर चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो या फ़िर चाहे न्यायाधीश, यही झल्लाहट देशी-विदेशी पूंजीपतियों पर नहीं दिखाते हैं। उन्हें लाखों करोड़ रुपये की छूटें दी जाती हैं। वे सरकारी बैंकों से लिया गया कर्ज नहीं चुकाते। वे न्यायालय के आदेशों को ठुकरा देते हैं पर सब चुप लगा जाते हैं। तब ये सब अर्थशास्त्र और राजनैतिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान बन ज्ञान बखारते हैं।

भारत ने जब से लोक कल्याणकारी राज्य का लाबादा उतारा है निजीकरण-उदारीकरण-वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया है तब से सरकार हो या न्यायालय सभी का एक सा रुख है। जनता की मांगों की उपेक्षा करो। जो कुछ लोक कल्याणकारी नीतियां ली या फैसले दिये जाते थे उन्हें भी अब वह लेना चाहता है।

खैर! न्यायाधीश महोदय! जनता तो आपकी सलाह के बगैर भी प्याज के बारे में अपना फैसला ले लेगी लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आपकी रसोई से उठती प्याज की तीखी गंध आपके विवेक की जगह ले ले। 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय के शासकों का इस तरह से कहना कि 'अगर जनता के पास रोटी नहीं है तो वह केक खा ले' की कीमत आपके वर्ग के लोग़ों को भी नहीं उन्हीं की तरह न चुकानी पड़े।

-नागरिक